

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—240 / 2017 / 223 (2017 / 00240)

1. श्रीमती मुन्नी देवी बेवा नृसिंह, पुत्रवधु स्व० कालूराम,
2. पवन पुत्र स्व० नृसिंह,
3. सुखपाल पुत्र स्व० नृसिंह,
4. सुश्री मिनाक्षी पुत्री स्व० नृसिंह,
5. श्रीमती सायरी देवी बेवा कालूराम,
समस्त जाति साधू, निवासी ग्राम पीसांगन, तह० पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गंगादेवी पुत्री स्व० कालूदास, पत्नी हनुमान दास वैष्णव, निवासी गढ़ी मालियान मंदिर के पास, अजमेर ।
2. श्रीमती नानी देवी पुत्री स्व० कालूदास, पत्नि बंशीदास वैष्णव, निवासी चैनपुरा मौहल्ला, ग्राम पीसांगन, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती रामा देवी पुत्री स्व० कालूदास पत्नि किशनगोपाल वैष्णव, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती श्यामा देवी पुत्री कालूदास, पत्नि सत्यनारायण वैष्णव, निवासी ग्राम भगवानपुरा, पुष्कर, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती मीरा पुत्री स्व० कालूदास, पत्नि लक्ष्मण वैष्णव, नि० बालाजी मंदिर के पास, शास्त्री नगर, अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 15.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 47 / 2011.

उपस्थित:—

1. श्री मनीष रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री एन०एस० राजावत, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 व 5.
3. रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पोंडेंट संख्या 6.

निर्णय

दिनांक:— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एव डिक्री दिनांक 15.5.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 ने अधी०न्याया० में वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पेश कर निवेदन

किया कि ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 1913 रकबा 5-2-10 नवीन खाता संख्या 524 के नवीन खसरा नंबर 3582 रकबा 0.83 है, खसरा नंबर 1968 रकबा 5-2-10 के नवीन खसरा नंबर 0.83 है, खसरा नंबर 1978 रकबा 4-8-00 के नवीन खसरा नंबर 3590 रकबा 0.71 है एवं खसरा नंबर 1980 रकबा 2-5-00 के नवीन खसरा नंबर 0.36 है बने हैं। विवादित भूमि के मूल खातेदार एवं वादीगण के पिता कालूदास वल्द शंकरदास का स्वर्गवास दिनांक 10.4.1997 को हो जाने पर उनके विधिक वारिसान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 1 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के स्व० पति एवं पिता श्री नृसिंह पुत्र है। वादीगण के पिता कालूदास पुत्र शंकरदास का स्वर्गवास होने के पश्चात् वादीगण के भाई स्व० नृसिंह द्वारा तथ्यों छिपाकर गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण विरासत नामांतरण संख्या 200 दिनांक 7.9.1998 को वादीगण की माता श्रीमती सायरी देवी प्रतिवादी संख्या एवं स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 4.7.2008 को नृसिंह का स्वर्गवास हो जाने पर गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर 1/2 हिस्सा जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम अंकित कर दिया गया। इसी प्रकार गैर कानूनी इन्द्राज के आधार पर अंकित 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती सायरी देवी से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गैर कानूनी रूप से पंजीकृत हक-त्याग विलेख दिनांक 30.12.2008 अपने पक्ष में निष्पादित करवाते हुए संपूर्ण कृषि भूमियों का जरिये नामांतरण संख्या 778 दिनांक 10.2.2009 से अपने नाम अंकित करवा लिया है। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 स्व० कालूदास की विधिक वारिसान एवं पुत्रियां होने से भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधि० 1956 एवं संशोधित अधि० 2005 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पैतृक कृषि भूमियों के समान सहहिस्सेदार होकर प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा निहित है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात में 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विद्वान अधी० न्याया० ने अपने निर्णय दिनांक 15.5.2017 को पारित कर वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित की। अधी० न्याया० के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया। रेस्पों के उपस्थित होने तथा अधी० न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी० न्याया० का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी० न्याया० द्वारा पत्रावली पर अपीलांटस का प्रस्तुत जवाब एवं वादिया/प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो कि अन्यन्त गंभीर आरोपों के साथ वादिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पर गौर न कर एवं उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधी० न्याया० द्वारा पत्रावली पर [अपीलांटस/प्रतिवादीगण](#) द्वारा अपने जवाबदावे में श्रीमती सायरी देवी बेवा कालूदास द्वारा मुन्नीदेवी बेवा नृसिंह के हक में अपने अंश व हिस्से की 1/2 भूमि बाबत निष्पादित पंजीकृत हक विलेख को सिविल न्यायालय से निरसत कराये बिना जारी की गई निर्णय व प्राथमिक निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी० न्याया० द्वारा अपीलग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व अभिलेख पर मौजूद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, गिरदावरियों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है।

विद्वान वकील अपीलान्टस ने बहस में यह भी कथन किया कि अधीन्याया ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम किये बिना तथा अपीलान्टस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र सरसरी तौर पर वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये है जो विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीन्याया का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधीन्याया को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलान्टस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधी पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बाबत् उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलान्टस को कोई सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलान्टस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अपीलान्ट संख्या 1 विधवा स्त्री है जिसको कानून एवं विधि की जानकारी नहीं है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही अपीलान्टस ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश कर दी है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
6. विद्वान वकील रेस्पो संख्या 1, 2 व 5 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विद्वान अधीन्याया का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस के पैरा संख्या 7 में वर्णित अभिकथन अपने जवाब वाद एवं मूल अपील में वर्णित अभिवचनों के तहत उल्लेखित नहीं किये गये है । इस कारण अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस के पैरा संख्या 7 में वर्णित विधिक आधार आदेश 6 नियम 1 जादी के तहत वर्णित होकर अपील निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी निवेदन किया जाना उचित एवं पर्याप्त होगा कि [वादीगण/रेस्पो](#) द्वारा लिविंग कोपार्सनर के विधिक आधार पर मूल वाद प्रस्तुत किया गया है जिसको स्वीकार किये जाने में अधीन्याया ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है । बहस में आगे यह भी कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस में मुख्य आधार यह प्रस्तुत किया है कि [वादीगण/रेस्पो](#) द्वारा विरासत नामांतरण एवं हक त्याग विलेख के आधार पर स्वीकृत नामांतरण को चुनौती नहीं दी गई है जबकि वादीगण द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 के तहत गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण नामांतरण को चुनौती दी है इस कारण उक्त नामांतरणों के विरुद्ध पृथक से अपील प्रस्तुत करन चुनौती दिये जाने की आवश्यकता नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार कालूदास रहे है जिनका स्वर्गवास दिनांक 10.4.1997 को हुआ । स्वर्गवास की दिनांक को [वादीगण/रेस्पो](#) जायंदा विवाहित पुत्रियां होकर विद्यमान करती थी, परन्तु उनके भाई नृसिंहदास द्वारा विरासत नामांतरण केवल मात्र माता श्रीमती सायरी देवी एवं स्वयं के नाम नामांतरण संख्या 200 दिनांक 7.9.1998 को स्वीकृत करवा लिया गया तथा उक्त गैर कानूनी इंद्राज के आधार पर श्रीमती सायरी देवी से वर्तमान अपीलान्टस द्वारा त्याग विलेख दिनांक 30.12.2008 को निष्पादित करवाया जाकर नामांतरण संख्या 778 दिनांक 10.2.2009 विधि विरुद्ध रूप से स्वीकृत करवाया गया है जबकि हक त्याग को धारा 63 राजकाशत अधी के तहत परिभाषित नहीं किया गया है । इस प्रकार प्रारंभतः अवैध एवं शून्य दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने की आवश्यकता नहीं होकर अपीलान्टस द्वारा अपील के माध्यम से उठाये गये विधिक आधार साहरीन होने से अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने योग्य है । उत्तराधिकार अधी 1956 दिनांक 2.6.1956 को प्रभाव में आया तथा उसमें संशोधन कर धारा 6 के तहत सन् 2005 में पुत्रियों को पुत्रों के समान रूप से

अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार वादीगण लिविंग कोपार्सनर होने के आधार पर अपने पिता की सम्पत्ति में 1/7, 1/7 हिस्सा निहित करता है। जिसकी घोषणा खातेदारी एवं विभाजन की आज्ञापति पारित करने में अधीन्याया ने किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गई है। बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन में कहीं पर भी निर्णय व डिक्री की जानकारी की तिथि एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने की तिथि का उल्लेख नहीं किया है। अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे उचित एवं पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन खारिज किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते हैं। हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधीन स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकेन किया गया। [वादीगण/रेसपो](#) ने अधीन्याया में वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि के मूल खातेदार एवं वादीगण के पिता कालूदास वल्द शंकरदास का स्वर्गवास दिनांक 10.4.1997 को हो जाने पर उनके विधिक वारिसान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 1 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के स्वपति एवं पिता श्री नृसिंह पुत्र हैं। इस प्रकार विवादित आराजियात पैतृक होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधीन के प्रावधानों के अनुसार रेसपो का भी विवादित आराजियात में समान हक व अधिकार निहित होकर [वादीगण/रेसपो](#) का विवादित आराजियात में 1/7, 1/7 हिस्सा है। वाद प्रस्तुत होने पर अधीन्याया ने जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया। वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थीया/वादिया रामादेव ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया रामदेवी उर्फ रामेश्वरी देवी पुत्री कालूदास पत्नि किशनगोपाल जाति साधू हाल निवासी देलवाड़ा तहल ब्यावर के फर्जी हस्ताक्षर कर के उपकरण में वादिया बनाया गया है जबकि वादिया ने अपने पिता की चल-अचल सम्पत्ति से कभी भी न तो हिस्सा चाहा है एवं न ही भविष्य में कभी कोई हिस्सा चाहुंगी। अतः मेरा उक्त प्रकरण में से निरस्त करवाने की कृपा करावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीन्याया मिसल वास्ते अग्रिम कार्यवाही के पूर्व निर्धारित दिनांक 11.6.2014 को नियत की। तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में चलती रही तथा सरकार परोकार ने समय हेतु जवाब चाहा। अधीन-न्याया के समक्ष प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई इस संबंध में अधीन्याया की पत्रावली पर किसी प्रकार का आदेश मौजूद नहीं है। अधीन्याया की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि अधीन्याया द्वारा अपीलांटस की तलबी पूर्ण हुए बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीन्याया के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीन्याया ने [वादीगण/रेसपो](#) का वाद विस्तृत विवेचन, विश्लेषण किये बिना तथा [अपीलांटस/प्रतिवादीगण](#) को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना तनकियात कायम किये एकतरफा में पारित किया है। यह विधि का सुस्थापित

सिद्धांत है कि जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी०न्याया० ने केवल मात्र सरसरी तौर पर वादीगण/रेस्पों के कथनानुसार वाद को डिक्री करने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधी०न्याया० विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.5.2017 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर